

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक 03 जून, 2015

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की अंशपूजी योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 156 दिनांक 13 मई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निगम द्वारा संचालित योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या-645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015 में निर्गत दिशा-निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि "अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूजी" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता संबंधी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र व्यय विचलन से कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में, विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में धनांबटन हेतु सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से वित्त विभाग की पूर्व सहमति अवश्य ली जायेगी। कतिपय प्रकरण जिनमें पहली बार व्यय किया जा रहा हो उनके सम्बन्ध में भी धनांबटन वित्त विभाग की सहमति से ही निर्गत किया जायेगा। मानक मद 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता तथा मानक मद 42 अन्य व्यय (जिला योजना, वाह्य सहायतित योजनाओं, केन्द्रपोषित योजनाओं एवं स्थानीय निकायों को समनुदेशन को छोड़कर) अन्तर्गत धनांबटन वित्त विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 (लेखानियम आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किशतों में किया जाय।
9. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 आयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द लिखा जाय, अन्यथा महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
10. बी.एम.-4 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएँ नियमित रूप से शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4250-00-800-04-अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूजी योजना के मानक मद-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
12. यह आवंटन अनुदान संख्या-15 के अलोटमेंट आई डी संख्या-S1506150186 दिनांक 26 जून, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 996 / XVII-3/14-08(स0क0)/2004 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,
(बी0एस0 बोरा)
अनु सचिव।